

Court No. - 34

Case :- WRIT - C No. - 53889 of 2012

Petitioner :- Alok Mishra And Another

Respondent :- Central Information Commission And Others

Petitioner Counsel :- Raj Kamal Singh

Respondent Counsel :- A.S.G.I.

Hon'ble Sunil Ambwani,J.

Hon'ble Aditya Nath Mittal,J.

1. We have heard learned counsel appearing for the petitioners. Sri R.B. Singhal, Assistant Solicitor General of India assisted by Sri Ashish Kumar Dubey, appears for the respondents.
2. The petitioners are practising advocates of this Court and are residing at 10-B Patrika Marg, Civil Lines, Allahabad. They have filed this writ petition for a writ of mandamus directing the respondents to provide the information sought by the petitioners vide their application dated 14.12.2011 under (The) Right to Information Act, in a time bound stipulated period, as may be fixed by this Court.
3. The petitioners in their application dated 14.12.2011 sent to the Director/Public Information Officer, North Central Zone Cultural Centre, 14 C.S.P. Singh Road, Allahabad have sought information on fourteen questions. It is alleged that since no reply was received within 30 days as provided in Section 7(i) of the Right to Information Act, 2005, the petitioners preferred an appeal to the Appellate Authority on 17.1.2012, and thereafter a second appeal under Section 19 (3) to the Second Appellate Authority. The petitioners, it is alleged have not received the information, giving rise to this writ petition.
4. In order to appreciate the points raised in this writ petition, the 14 questions asked by the petitioners in Hindi are quoted as below:-

“1. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक इलाहाबाद केन्द्र की कार्यक्रम समिति 2009 के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने के साथ यह बताने का कष्ट करें कि क्या निदेशक “कार्यक्रम समिति कके सदस्यों को बदलने का अधिकार है? यदि हाँ तो नियम उपलब्ध कराने के साथ वर्ष 2009 से 2011 दिसम्बर

तक कार्यक्रम समिति की बैठक की कार्य सूची में न होते हुये, कौन-कौन से कार्यक्रम प्रयोजित किये गये, धनराशि सहित विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. उ०म०क्षे०सां० केन्द्र में वर्ष 2009 जून से 2011 दिसम्बर तक प्रिन्टिंग, फोटोग्राफी, बस-टैक्सी, लाइट, साउण्ड में किस फर्म का टेण्डर अनुमोदन हुआ था? किस फर्म से बिना टेण्डर के कार्य कराया जा रहा है? विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही साथ प्रिन्टिंग, फ्लैक्स, फोटोग्राफी, बस-टैक्सी, लाइट-साउण्ड में किस को कितने लाख का भुगतान किया गया है। विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उ०म०क्षे०सां० केन्द्र वर्ष 2009 से 2011 दिसम्बर तक इलाहाबाद हाट एवं प्रेक्षागृह, कलाभवन आर्ट गैलरी में कितनी की आय हुई? उक्त धनराशि को किस मद में खर्च किया गया है? क्या दरों का निर्धारण गर्वनिंगबॉडी द्वारा किया गया है?

4. उ०म०क्षे०सां० केन्द्र द्वारा कार्यालय मरम्मत, साफ सफाई निदेशक आवास, मोबाइल, दूरभाष के साथ निदेशक कक्ष के मरम्मत के नाम पर कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा किस मद से भुगतान किया गया है साथ ही उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र में छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान किन कर्मचारियों/अधिकारियों को किया गया है। एवं किस मद से एरियर का भुगतान किया गया है। विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. उ०म०क्षे०सां० केन्द्र द्वारा वर्ष 2009 से 2011 दिसम्बर तक किन-किन कलाकारों, वादको, उपशास्त्रीय, शास्त्रीय, गजल, भजन, कौवाली, गुरु, फोटोग्राफी विडियोग्राफी कोरियोग्राफी तथा भिन्न-2 फर्मों का इनकम टैक्स काट कर आयकर कार्यालय में भुगतान किया गया है, नाम सहित विवरण उपलब्ध कराये।

6. वर्तमान निदेशक श्री आनन्दवर्धन शुक्ल को राजस्थान सरकार (गृह विभाग) ने किस विभाग में नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है? साथ ही उ०म०क्षे०सां० केन्द्र द्वारा मार्च 2009 में कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन बिल पर किस आहरण वितरण अधिकारी ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया। कृप्या उसका नाम एवं पद बतायें। इसकी प्रति उपलब्ध कराये।

7. उ०म०क्षे०सां० केन्द्र इलाहाबाद में माह मार्च दिनांक 01.03.2009 से 31.03.2010 तक के कुल कितने तथा किन-किन तिथियों को नगदी/चेक

भुगतान पत्रक द्वारा कितने धनराशि का समायोजन किया गया एवं समायोजनकर्ता अधिकारी के नाम एवं पद बताये।

8. उ०म०क्षे०सां० केन्द्र मार्च 2009 में नगदी/चेक भुगतान पत्रक पर मुख्य आहरण वितरण अधिकारी का पद एवं नाम बतायें जिनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, एवं श्री आनन्द वर्धन शुक्ल उ०म०क्षे०सां० केन्द्र, इलाहाबाद में कब और किस तिथि को कार्यभार ग्रहण किया गया।

9. उ०म०क्षे०सां० केन्द्र के निदेशक दिसम्बर 2009 से 2011 तक कितने दिन कार्यालय में कार्य किये तथा कितने अवधि तक दौरे पर रहे? निदेशक द्वारा ट्रेन ए.सी.—। हवाई जहाज से वर्ष जून 2009 से 2011 तक के यात्रा पर किनता धन खर्च किया गया है, कितने धनराशि का टिकट निरस्त कराया गया है, विवरण उपलब्ध कराये।

10. गवर्निंगबॉडी द्वारा 2009 के दौरान क्या गाड़ी नं. यू०पी० 70 ए.जी. 0693 मारुती सुजकी रिवाज्ट डिजायर के क्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई थी या नहीं साथ ही वर्ष 2009 मार्च से 2011 मार्च तक वित्तीय वर्ष समायोजन 31 मार्च को कुल कितने धनराशि आदि का समायोजन एक ही दिन (31 मार्च) में किया गया है तथा इसके पूर्व कितने धनराशि का समायोजन किया गया है, विवरण उपलब्ध कराये।

11. वर्ष 2009 से 2011 तक के गवर्निंगबॉडी मीटिंग में क्या-क्या अनुमोदन किया गया? सदस्यों को किस तिथि को अनुमोदन का पत्र भेजा गया, विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12. केन्द्र द्वारा लोक कलाकार, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, गायन, वादन, कोरियो ग्राफर नृत्य नाटक, गजल, कौवाल्ली, कवि, गुरु के मानदेय पर अलग-2 कितने लाख का बजट आदि रखा गया है तथा किस श्रेणी के कलाकार को हवाई जहाज तथा ए.सी. फर्स्ट का टिकट उपलब्ध कराया जाता है? कितना भुगतान का प्राविधान है? उपर्युक्त सभी विषय पर क्या भारत सरकार का कोई आदेश है या स्वयं निदेशक द्वारा भुगतान हेतु निर्णय लिया जाता है, विवरण उपलब्ध कराये।

13. इलाहाबाद हाट की मरम्मत हेतु भारत सरकार ने कितने धनराशि का अनुदान अब तक दिया है, इस राशि से कितने का व्यय शिल्प हाट की मरम्मत एवं रख-रखाव पर खर्च किया गया यदि इस राशि से कोई अन्य कार्य किये गये तो उसका विवरण उपलब्ध कराये।

14. उम0क्षे0सां0 केन्द्र द्वारा आक्टव 2009 से 2011 तक भारत सरकार एव जनजातीय मंत्रालय ने केन्द्र को कितनी धनराशि-प्रकृति 2011 में दी और केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि कार्यक्रम में व्यय किया गया, बजट सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।”

5. We find that the information on most of these questions, would virtually consume the entire staff of the centre for days altogether if not months, to collect and the compile information. We also find that most of the information sought has no concern with the petitioners, nor the petitioners can have or have shown any object or purpose for which they require the said information.

6. The purpose of Right to Information Act, 2005 is for bringing the transparency in functioning of public authorities. The object and purpose of the Act is to establish confidence in the public functional bodies and to ensure accountability and transparency in discharge of their duties. The Act does not provide for any reason to be given, or to show bona-fides in seeking information. The petitioners in this case have not chosen their rights under (The) Right to Information Act by approaching the State Information Commission, if they have not received the information within the time prescribed from the Public Information Officer or the Appellate Authority in the department. They have rather approached this Court under Article 226 of the Constitution of India for a direction to the respondents to provide information sought by the petitioners.

7. Once the petitioners have chosen to seek directions by filing a writ petition under Article 226 of the Constitution of India, which is a discretionary constitutional remedy to be used for bonafide purposes they must satisfy the Court, that they have approached the Court with bonafide purposes with clean hands.

8. We asked learned counsel appearing for the petitioners about their concern and purpose of seeking the information. The petitioners are practising advocates of the High Court. They have neither placed, nor

could explain the purpose to seek such information which will virtually block the functioning of the North Central Zone Cultural Centre at Allahabad. The petitioners are unable to give any reason, or object for seeking the information. The counsel appearing for petitioners has chosen to keep quite and did not answer on questions in spite of repeated requests.

9. Recently we have noticed a large number of writ petitions filed for enforcement of the remedies under the Right to Information Act, which has made it necessary for the Court in exercise of its powers under Article 226 of the Constitution of India, to review the object and purposes and also the methods opted by certain persons in seeking information. If the Court notices, in exercise of powers of issuing writ as extraordinary remedies, that the object and purpose is not bonafide, it can always refuse the relief.

10. In the facts and circumstances of the case in which no reason has been given by the petitioners we find that filing of this writ petition, is not for bonafide purposes. Instead of waiting for information to be given or to approach State Information Commission, under (The) Right to Information Act the petitioners have chosen to approach the High Court under Article 226 of the Constitution of India, seeking extraordinary remedies, which can be given only to the bonafide litigants. The information sought clearly appears to serve oblique purposes. On the response to our questions put to the counsel, it is apparent that the petitioners as young advocates have filed this writ petition as a proxy for any person who has some axe to grind against the respondents. The petitioners under the Advocates Act, are not supposed to act for such purpose for their clients.

11. This writ petition is accordingly dismissed.

Order Date :- 29.10.2012

Kpy